

अपने चारपहिया वाहन से वाहन
स्वामी सोनबरसा स्थित सरदारनगर
मार्ग पर पहुंचे, वहां आक्रोशित ग्रामीणों
ने गाड़ी पर पथराव कर उनकी गाड़ी
को क्षतिग्रस्त कर दिया और उनको
साथ हाथपाई भी की। सूचना मिल
पर मौके पर पहुंची सोनबरसा चौक
पुलिस ने वाहन स्वामी को वहां
निकाला। बाद में पुलिस ने हिरासत
में ले लिया।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

भारतीय बस्ती

बस्ती 6 जनवरी 2025 सोमवार

सम्पादकीय

पड़ोसी बांग्लादेश की उथल-पुथल

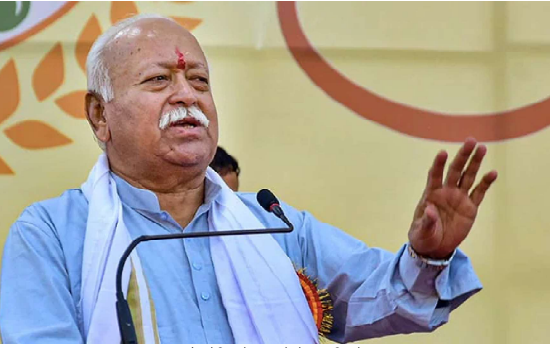
बांग्लादेश में उग्र छात्र आंदोलन के बाद जो स्थितियाँ बनी हैं वे न तो इस देश के हित में हैं और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में। जनविद्रोह की स्थितियों के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के पलायन के बाद लगातार बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंध मुजीबुर्रहमान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। जिसकी शुरुआत तब देखने को मिली, जब अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूसुफ ने पिछले साल 16 दिसंबर को निर्गोप विद्रोह यानी विजय दिवस के मौके पर दिए गए संबोधन में युवा राष्ट्र के संस्थापक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का उल्लेख तक नहीं किया। उल्लेखनीय है कि यह दिवस भारत में भी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1971 में जहां भारतीय रक्षा बलों के सामने पाकिस्तान की विशाल सेना के आत्मसमर्पण की याद दिलाता है, वहीं बांग्लादेश के दमन व अत्याचार से मुक्ति का भी दिन है। इस संदर्भ में मोहम्मद यूसुफ ने जहां अपरस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन को दुनिया के सबसे बड़े निरंकुश शासन के रूप में वर्णित किया, वहीं मुजीबुर्रहमान की पूरी तरह अवहेलना की। निश्चित रूप से यह देश के संस्थापक की उपेक्षा के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है। दरअसल, राजनीतिक दुराग्रह के चलते अंतरिम सरकार शेख हसीना के पिता की विरासत को भले ही मिटा न सके,लेकिन वो इसे कमजोर करने पर जरूर अमादा है। यहां तक कि शैक्षिक पाठ्यक्रम से भी छेड़छाड़ की जा रही है। कहा जा रहा है कि कार्यवाहक सरकार बांग्लादेश के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में बताएगी कि देश को आजाद कराने में मुजीबुर्रहमान ने नहीं बल्कि जियाउर रहमान ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही बांग्लादेश को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। इस तरह अराजकता व अल्पसंख्यकों पर हमलों के बीच नये विमर्श गढ़ने की कोशिश की जा रही है।

दरअसल, अंतरिम सरकार और कट्टरपंथी तत्व जनाक्रोश के चलते अपनी सुविधा का मुहाराब गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से बांग्लादेश मुक्ति अभियान के दौरान जियाउर रहमान एक सम्मानित सैन्य अधिकारी थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने 1971 के युद्ध में विशिष्टता के साथ सेवाएं दी थी। वे कालांतर बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी बने थे। अपदस्थ सरकार के कर्तव्यता दलीलें दे रहे हैं कि उनके योगदान को राष्ट्र द्वारा उचित रूप से सम्मान देना चाहिए। लेकिन हकीकत यह भी है कि इसके जरिये मुजीबुर्रहमान के योगदान को कम करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार करना अनुचित ही होगा। दरअसल, यह सिर्फ सत्ता के केंद्र में आए व्यक्तियों की बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है बल्कि बांग्लादेश में मुजीब के चित्र वाले नोटों को भी चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कुत्सित कोशिशें की जा रही हैं। निश्चित रूप से गलत दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि तमाम निर्णय कहीं न कहीं राजनीतिक दुराग्रहों से प्रेरित हैं। इसके बावजूद कि बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार खुद को बार-बार अराजनीतिक कहने से नहीं चूकती। यहां उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान की विधावा और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, फिलहाल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की प्रमुख हैं। जिसके साथ कार्यवाहक सरकार के मधुर रिश्ते हैं। वहीं सत्ता हासिल करने को बेताब बीएनपी चुनाव में हो रही दौड़ से भी बेचैन हो रही है। दरअसल, सरकार पर उन छात्र नेताओं का भी बड़ा दबाव है, जिन्होंने शेख हसीना को खिलाफ हूए आंदोलन का नेतृत्व किया था। जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। कालांतर उन्होंने भारत में शरण ली थी। असल में, छात्र नेता दबाव बना रहे हैं कि वर्ष 1972 के बांग्लादेश के संविधान को फिर लिखा जाए। वे संविधान को मुजीबिस्ट चार्टर बता रहे हैं। आरोप है कि इसी ने भारत की आक्रामकता का मार्ग प्रशस्त किया। निश्चित रूप से मुजीब विरोधी आलोचना और भारत विरोधी बयानबाजी मिलकर बांग्लादेश की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं पर पानी फेर सकती हैं। डाका को सलाह दी जानी चाहिए कि तब वो दिल्ली से रिश्ते खराब करे और न ही मुजीब को इतिहास के कबाड़ के हवाले करे।

—अवधेश कुमार—

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत द्वारा वर्तमान मंदिर-मस्जिद उमरते विवादों पर दिए वक्तव्य को लेकर अनेक धर्माबांवी और हिंदू संगठनों के नेताओं की विरोधी प्रतिक्रियायें लगातार आ रही हैं। इस संदर्भ में सबसे कड़ा बयान जगतगुरु स्वामी राममद्राचार्य जी का आया। उन्होंने कहा कि भागवत के बयान से पूरी तरह असहमत हूं। मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि भागवत हमारे अनुशासक नहीं हैं, बल्कि हम हैं। बाद में उन्होंने एक उल्लेखित पर बात करते हुए ऐसा कुछ बोला जो उनके अंदर व्याप्त नाराजगी को साफ दर्शा रहा था। वैसे राममद्राचार्य जी ने कहा कि संभल में अभी जो कुछ हो रहा है वह बहुत बुरा है। हालांकि सकारात्मक पहलू यह है कि बीज हिंदुओं के पक्ष में सामने आ रही हैं। हम न्यायालय में मतदान और जनता के समर्थन से इसे सुरक्षित करेंगे। वैसे अनेक संगठनों, बुद्धिजीवियों, नेताओं आदि ने डॉक्टर भागवत के बयान का समर्थन भी किया है। विडंबना यह है कि पहले जब सरसंघचालक ने ऐसे वक्तव्य दिए तब उसे झूठ, माखंड और आंखों में धूल ओढ़ने वाला तक कहा गया। इसलिए विदेशियों की प्रतिक्रियाएं इन संदर्भों में न नैतिक हैं, न विश्वसनीय और न इनका कोई अर्थ है। हमें पूरे विश्व को सही संदर्भ में देखना और निकष निकालना होगा।

पिछले वर्षों में यह पहली बार नहीं है जब भागवत के वक्तव्य पर विरोधी तीखी प्रतिक्रियाएं हिंदू संगठनों, नेताओं और कुछ धर्माबांवी की ओर से आया है। 12 जून, 2022 को नागपुर में जब उन्होंने कहा था कि अयोध्या, काशी और मथुरा की मान्यता रही है लेकिन हर मस्जिद में मंदिर क्यों तलाशें तब भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं थीं और उसके पूर्व बहमं संसदों में दिए गए आक्रामक वक्तव्यों के संदर्भ में भी उनके विचारों को कुछ पुराने में विरोध किया था। ऐसा नहीं है कि संघ प्रमुख या संघ के शीर्ष नेतृत्व को इसका आभास



पहले से नहीं होगा। बावजूद उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया और पहले भी देते रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे गहरी सोच, अतीत और वर्तमान का विश्लेषण तथा भविष्य की दृष्टि होगी। हम संघ के विचारों या कुछ कार्यों से सहमत असहमत हो सकते हैं लेकिन निष्पक्ष होकर विश्लेषण और विचार करने वाले मानते हैं कि शीर्ष स्तर से दिया गया हर वक्तव्य और भाषण काफी सोच-समझकर ही सामने आता है। वैसे भी सरसंघचालक का वक्तव्य संगठन परिवार के लिए अतिम शब्द माना जाता है। स्वाभाविक ही जब ऐसा बात रहने से तो देश में बने वातावरण, जिसने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई तथा मथुरा और काशी को लेकर भी उसके मत उन दिनों से स्पष्ट रहे हैं जब दूसरे संगठनों का प्रभाव नहीं था, या वे थे नहीं तो वह ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वह भी उन स्थितियों में जब संभल से लेकर बड़ौदा वाराणसी दिल्ली भोजपाला आदि सभी जगह ऐतिहासिक रूप से घटनाएं आए वर्तमान स्थिति हिंदुओं के पक्ष में जाती है। मुस्लिम संघ में इन मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उसमें निहित प्रतियोगों को अमान्यित करने के लिए अनेक उपायों से स्वतंत्रता के बाद भी अपने ही मूल शाहर से हिंदुओं को

दूसरी जगह पलायन करना पड़ा उनमें मंदिरों में पूजा पाठ करना, लोगों का जाना कठिन हुआ, बंद हुए और कई जगहों पर बेदरती से स्थलों को कब्जा करने के उपक्रम भी हुए। स्थानीय स्तरों पर इनमें से ज्यादातर स्थानों को प्राप्त करने की भावना या उन मुद्दों को उठाने और कहीं-कहीं संघर्ष करने का भी लंबा अतीत है। इसमें अगर व्यक्तिगत रूप से किसी हिंदू समूह या पूरे समाज को लगता है कि हमें यह स्थल वापस मिलने चाहिए और जहां प्रतिभाओं का अपनाना हुआ उनका निराकरण भी हो और इसके लिए वे सामने आते हैं, न्यायालय में जाते हैं तो यह स्वाभाविक है। भागवत जिस विश्व पर बोल रहे थे वह भारत के विश्व गुरु बनने पर था और उनका पूरा भाषण 1 घंटे से ज्यादा का है। इसमें वह प्रतीकों के बीच मुस्लिम का काल, अंग्रेजों की गुलामी आदि के प्रभाव, वर्तमान में भारत किस तरह विश्व दृष्टि से कम कर रहे हैं आदि सभी बातें शामिल हैं जिसकी लोग अपेक्षा रखते हैं। फिर भविष्य की दृष्टि है और उसी में लगभग अंत में केवल एक कुछ पंक्तियां हैं। किसी देश को पूरा संसार अपना आदर्श नहीं मानेगा और उसका अदृश्यरूप भी करेगा जब वह देश अपने अंदर विकास को सही तरीके से सुलझाने, सभी पक्षों, महजबों के बीच के तनावों

को तरीके से समाप्त करने और सहजीवन के साथ रहते हुए आदर्श देश की मिसाल रखेगा। यानी उदाहरण के रूप के अन्य पहलुओं पर गहराई से नहीं विचार होगा तो समस्यायें सुलझने के बजाय उलझनी और फिर इनका समाधान भी संभव नहीं होगा। कोई भी विकेकीली व्यक्ति इनका करण को जो अतीत में अन्याय, अन्याचार, ध्वंस और कब्जे हुए वो वैसे ही रहे और लोगों की भावनाएं पर दमिती हो। इनसे भविष्य में हिसा व तनाव बढ़ाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। समस्या यह है कि संपूर्ण देश में ऐसे हजारों स्थान हैं। कल्पना करिए धीरे-धीरे पूरे देश में ऐसे विषय उठ जाएं और स्थिति संभल जैसी पैदा हो तो क्या होगा? क्या देश की इन विवादों के अंतिम समाधान की अभी तक तैयारी हो? क्या हिंदू समाज इनके विरुद्ध होने वाली अनेक तरह की विपरीत प्रतिक्रियाओं का सफलतापूर्वक सामना करने की अवस्था में पहुंच गया है? क्या जो लोग इन विषयों को न्यायालय में ले जा रहे हैं उनकी ऐसी क्षमता है कि वो इनका सामना भी कर सकें? क्या उन सब की विश्वसनीयता है? क्या धर्माबांवी और अन्य हिंदू संगठनों ने उन स्थितियों के लिए अपनी तैयारी कर रखी है? अभी तक ज्यादातर 6 धर्माबांवीयों ने संगठित होकर किसी ऐसे विषय के समाधान की न पलक भी न लोगों के बीच गए। संभल में ही समस्या पैदा होने पर कितने समाधान या संघर्ष के लिए आए हुए हैं? अभी तक अवश्य दृष्टि लिए। संप्र प्रश्नों का उत्तर भारत के व्यापक राष्ट्रीय वैश्विक लक्ष्यों का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्ण तलाश से जाने की आवश्यकता है। संघ यह है कि लगभग 1000 वर्षों की हिंदू मुस्लिम विवादों के समाधान पर देश के राजनीतिक, धार्मिक और वैश्विक नेतृत्व ने कभी लंबा विचार ही नहीं किया और जब विचार नहीं होगा तो फिर रास्ता निकालेगा? कैसे विपरीत राजनीतिक दलों ने डाट के लिए अपने बयानों और नीतियों से अतीत या वर्तमान के अन्यायों की समर्पण किया और जो इन विषयों को उठा

डॉक्टरों की कमी के खपन



—डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी—

सर्वविदित है कि देश की विशाल आबादी पर चिकित्सकों की उपलब्धता वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है। मुरस्को कई बार बता चुका है कि भारत के कई स्थानों पर एक हजार व्यक्तियों पर एक चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि देश के कई मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रह जाएं तो इस देश के लिये विडंबना ही कहा जाएगा। इस ज्वलंत मुद्दे पर देश की शीर्ष अकादमिक ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि इस माह में अक्टूबर के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में रिक्त पड़ी सीटों को तुरंत भर जाए। जाहिर है जब देश में पहले से ही डॉक्टरों के कमी है तो ये सीटें क्यों खाली जा रही हैं? निश्चित रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में शीर्ष अकादमिक की यह पहल बलापूर्वक सराबोर हो सकती है। फरवरी 2024 को लोकसभा में एक वक्तव्य के जवाब में मंत्रालय की ओर से नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई, इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जून 2022 तक स्टेट मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन ने 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जून 2022 तक स्टेट मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन ने 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। देश में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए पिछले दिनों बड़ी संख्या



में नये मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन इनमें सीटों की संख्या दुगुनी हो जाने के बाद भी डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में कार्ययार संचालन के बाद से विशेष उपचार के लिए एक दर्जन से अधिक एन जेस चिकित्सा संस्थानों का निर्माण किया है। सरकार की देश के 761 जिलों में से हरके में कम से कम एक बड़ा अस्पताल बनाने की योजना है। समस्या डॉक्टरों की कमी की है। यह कमी तब और गंभीर हो जाती है जब भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1991 में भारत का डॉक्टर-प्री प्रति व्यक्ति 1,000 लोगों पर 1.2 डॉक्टरों के रिकॉर्डों के साथ स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी 2020 में अनुपात घटकर लगभग 0.7 रह गया। डब्ल्यूएचओ द्वारा सफाई रिपोर्ट एक है और चीन में यह अनुपात 2.4 है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मार्च में संसद को संबोधित किया वारत में प्रति व्यक्ति 834 रोगियों पर एक डॉक्टर का अनुपात है, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा स्थापित है, लेकिन संख्या में आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सक शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ

और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे डॉक्टर समूह अपनी गिनतों में पारंपरिक चिकित्सा के चिकित्सकों को शामिल नहीं करते हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा काम हुआ है। एक संसद में यूपी में रिकॉर्ड 18 मेडिकल कॉलेज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश और सूक्ष्म लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के चलते आज राज्य में 64 जिलों में कम से कम एक चिकित्सक स्थिति हो चुके हैं। जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी के बचे हुए जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। असल में यूपी में योगी सरकार एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज के प्रण को पूरा करने की दिशा में बढ़ती तेजी से काम कर रही है। सरकारी अंग्रेजी से पता चलता है कि मोदी के कार्यकाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर, सार्वजनिक अस्पतालों की संख्या में लगभग नौ करोड़ की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने स्थानीय और सार्वजनिक कॉलेजों में चिकित्सक की संख्या में मेडिकल सीटों की संख्या मार्च 2014 से पहले 51,348 जो स्तर लगभग दोगुनी कर 1,01,043 कर दी है।

डालर के मुकाबले रुपये में गिरावट का सिलसिला



—डॉ.सत्यवान सोहर—

सितंबर 2024 के शंकर शिखर के बाद निरंतर बहिर्बाहें ने रुपये को कमजोर कर दिया क्योंकि निवेशक अमेरिकी व्याज दरों में वृद्धि की अटकलों के बीच सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर चले गए। उच्च व्यापार घाटे जैसे व्यापार घाटे आयात पर बाहरी निर्भरता को उजागर करते हैं, विशेष रूप से ऊर्जा के लिए, रुपये की कमजोरी के दौरान चालू खाता घाटा बढ़ाते हैं। रुपये के अत्यल्पन के साथ भारत का कच्चे तेल का आयात बिल बढ़ गया, जिससे 2024 का व्यापार घाटा बढ़कर +75 बिलियन के करीब पहुंच गया। टैरिफ की धमकियां और ब्रिक्स मुद्रा विवाद जैसी वैश्विक घटनाएं भारत के बाहरी व्यापार और निवेश के लिए अनिश्चितताएं पैदा करके अस्थिरता को बढ़ाती हैं। ब्रिक्स देशों की मुद्रा योजनाओं के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की 2024 टैरिफ घोषणा ने बाजार में विचलना को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की बाहरी स्थिरता कमजोर हुई। रुपये को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा मंत्रालय ने भारी निर्यात निरंतर वैश्विक बाजार अस्थिरता के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक लचीलपन को प्रतिबोधित करती हैं। रुपये को वापस 85.53 पर लाने के लिए दिसम्बर 2024 में एक ही तिमाही में +20 बिलियन से अधिक के मंडार को समाप्त कर दिया। कमजोर रुपया घटते मीडिक नीतियों को प्रतिबोधित करता है, मग्रे आयातों के माध्यम से मुद्रास्फीति को बढ़ाता है जबकि विकास सम्बन्धी विताओं को दूर करने के लिए राजकोषीय स्थानों को कम करता है। दिसम्बर



2024 में कच्चे तेल के आयात की लागत 15: बढ़ गई, जिससे नीति निर्माताओं पर मुद्रा प्रबंधन और राजकोषीय विस्तार रणनीतियों को प्रभावी ढंग से संतुलित करने का दबाव पड़ा। टैरिफ या प्रतिबंध जैसे अर्थव्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष अस्थिरता पैदा करते हैं, जिससे सुरक्षित-पनाहगाह डॉलर की मांग बढ़ती है और उपभोक्ता बाजारों की मुद्राएं कमजोर होती हैं। विश्व-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे भारत के आयात बिल पर दबाव पड़ा और रुपये का मूल्य कम हुआ। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा मंदी के कारण भारत से यू.पी. का बहिर्बाहें होता है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है। निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ने से विश्व मुद्रा का बहिर्बाहें बढ़ता है, जिससे रुपया कमजोर होता है। कच्चे तेल और सोने के बढ़ते आयात के कारण 2022 में भारत का रिजर्व आयात घाटा रुपये के मूल्यदास को बढ़ाता है। उच्च परतें मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्य को कम करती हैं, जिससे निर्यात कम प्रतियोगी हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। कच्चे तेल जैसे अत्यंत आवश्यक आयातों के निर्यात में बाजार में अस्थिरता बिलों को बढ़ा दिया, जिससे 2023 में माध्यम से मुद्रास्फीति को बढ़ाता है जबकि विकास सम्बन्धी विताओं को दूर करने के लिए राजकोषीय स्थानों को कम करता है। दिसम्बर

जिससे मुद्रा प्रवाह हतोत्साहित होता है और 2024 के वित्तीय प्रदर्शन में कमी और स्टॉक वैल्यूकरण में वृद्धि के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बहिर्बाहें हुआ। मुद्रा को स्थिर करने के लिए केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाते हैं और केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं। दिसम्बर 2024 में आरबीआई के स्तर से हस्तक्षेप ने रुपये को अस्थायी रूप से 85.53 प्रति डॉलर पर स्थिर करने में कामयाबी हासिल की। राजकोषीय रूप से विश्व निवेशकों की प्रवृत्ति को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता को कम करती है, जिससे मुद्रा स्थिरता में विश्वास कमजोर होता है। महामारी के दौरान भारत के रिजर्वों राजकोषीय घाटे ने बाहरी लचीलपन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपायों को सीमित कर दिया। मुद्रा नीतियों पर सरकार का स्पष्ट रूप निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और सहा दबाव कम करता है। आरबीआई जनरल एप्रिल 2024 में डी-सॉल्वेंसी के कारण को खारिज करने से बाजार, आश्वासन हुआ, जिससे रुपये के मूल्यदास की क्षितिर् अस्थायी रूप से कम हो गई। लाघ लचीलपन को मजबूत करने के उपाय हैं, निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा आप्र बढ़ाने और व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए मूलवर्धन विनिर्माण और सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करना। फार्मास्यूटिकल और आईटी जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने से व्यापार को कम करने और रुपये को स्थिर करने में मदद मिल सकती है।

महिला की हत्या व हत्यारोकथी के फाँसी लगाकर जमाना देने के मामले में नई कहानी निकल कर सामने आई है। हत्या के दो दिनों पहले ही हत्यारोकथी के सीमा लगाकर आन्ध्रप्रदेश सरकार की काशिका की थी लेकिन जमाना करके एक घण्टी में भी नहीं बुझा कर उसकी जमाना बचा ली थी महाराष्ट्र का क्षेत्र भिन्नता के कोठवाड़ा गांव निवासी सीमाजी सोनीनी (38) की इसी गांव निवासी छगगुन (42) ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। साथ ही हत्या करने के बाद उसने खुदी भी फाँसी के फाँस से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बांधों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पर देर रात सीमा की चाचा शनि देर जाया गया और संस्कार कर दिया गया। दो मौतों के बाद मामले में हत्या व आन्ध्रप्रदेश की कानून व्यवस्था के बीच का कौनसा कौनसा कथं तथ्य सामने आए है। बताया जाता है कि जनवरी 2022 में घातक

पाया गया है। सूत्रपुत्र इलाके की एक कर्म से लिया गया तिनी के बावला का नमूना फेल हो गिनी के मिला। मिला बाजार इलाके की एक कर्म से लिया गया ब्राडेड पनीर की नमूने में मी मिलावट की मुद्रि हुई है। रातगीरन चोरों की एक इकाय से लिया गया पनीर का नमूना मी अमामानक मिला है। नमूना में सरसे अधिक विकर वाला सादुनामा में धावाज भंडा मिला रहे हैं। वहीं, पनीर कपडा में तो पाजडर से साथ-साथ कपडा धोने में इस्तेमाल होने वाले एक स्विचिड का प्रयोग हो रहा है। इस्से न सिरिउ सरसे विकरवां नही रहते हैं, बल्कि जांच में वह कपडा मी नही जाता।

जानकार बताते हैं कि सरसे अधिक सादुनामा की आपूर्ति तिलिनालुन से होती है। बाह्य कसाया की खेती होती है। शहरकन जैसे

इसके मूल को निकालकर पीसकर पेस्ट बनाया जाता है। इस्त पेस्ट को सुखाकर एक समान दान बनाए जाते हैं। सुखिइ सरसे कर्वाहाइइसर की मात्रा अधिक होती है, इस्तोएए इतर करने वालों को इस्से उर्जा मिलती है।

इसमें फाहवर की अधिकता और कैलोरी कम होने से इस्से खाने से धन क्रिया में रुकी रहती है। इस्की कमिड को देखते हुए धोखाजो ने इस्से मैदा मिलाकर बेचना शुरू कर दिया है। सरसे अधिक पनीर-खोया में मिलावट र जाज में सरसे अधिक मिलावट खोया और पनीर के नमूनों में मिले हैं। विमगाण्य सूत्र बताते हैं कि व्यापारतर पनीर में दूध की मात्रा नहीं है। पनीर की जगह उतसे पाजडर मिला है। इसका जगह को पनीर बनाकर लिपि इस्से कम देगे वालो इस्से उर्जा को जाला जाता है।